International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

|ISSN: 2582-7219|

Volume 2, Issue 6, June 2019

वर्तमान में भारत- अमेरिकी संबंधो के बदलते आयाम - एक: विश्लेषणात्मक अध्ययन

Rajesh Gupta

Assistant Professor in Political Science, B.S.R. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

सार

भारत-अमेरिका संबंध द्विपक्षीय सहयोग साझा करते हैं। यह व्यापक-आधारित और बहु-क्षेत्रीय है, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उच्च-प्रौद्योगिकी, असैनिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य शामिल हैं। अमेरिका भारत का सबसे व्यापक रणनीतिक साझेदार है और दोनों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वर्तमान परिदृश्य में, भारत-अमेरिका संबंध बहुत करीबी और अच्छे हैं। वास्तव में, भारत और अमेरिका एक साथ कई आयोजनों और सम्मेलनों में भाग लेते हैं और कई मुद्दों पर एक साथ खड़े होते हैं जैसे कि आतंकवाद का मुकाबला और दोनों आमतौर पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के प्रति अविश्वास साझा करते हैं। भारत और अमेरिका अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ अपने विश्वास और दोस्ती का प्रदर्शन करते रहते हैं।किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी के लिए, उम्मीदवारों को विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को जानना होगा। यहां हम भारत-यू.एस. द्विपक्षीय संबंध की चर्चा करेंगे । इस लेख में भारत-अमेरिका संबंधों के प्रमुख पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।भारत-यू.एस. साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते अभिसरण के आधार पर द्विपक्षीय संबंध एक "वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" के रूप में विकसित हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से, यू.एस. ने भारत की शक्ति के विकास के लिए एक द्विपक्षीय दृष्टिकोण बनाया। एक ओर, इसने भारतीय स्थिरता को महत्व दिया और उन पहलुओं को बढ़ावा दिया जो इसके बड़े हितों की सेवा करते थे। यह उस समय अमेरिका की उदारता की व्याख्या करता है जब विकास कार्यक्रमों की बात आती है जब हमारे राजनीतिक संबंध अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं थे। जब 1962 जैसी गंभीर चुनौतियां थीं, तो अमेरिकी नीति निर्माता वास्तव में हमारे भविष्य को लेकर चिंतित थे। लेकिन दूसरी ओर, उन्होंने हमारे क्षेत्रीय प्रभुत्व को बेअसर करने के लिए काम किया, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ कुछ समानता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की।

भारत में नई सरकार द्वारा विकास और सुशासन पर जोर देने से द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने और नए आदर्श वाक्य "चलें साथ साथ: फॉरवर्ड टुगेदर वी गो" के तहत सहयोग बढ़ाने का नया अवसर पैदा हुआ है, जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शिखर सम्मेलन के बाद 30 सितंबर 2014 को वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ अपनाया गया था। । उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान ने द्विपक्षीय सहयोग को निरंतर गति प्रदान की है, जबकि व्यापक और निरंतर विस्तारित संवाद वास्तुकला ने भारत-यू.एस. के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा स्थापित किया है। आज भारत-यू.एस. द्विपक्षीय सहयोग व्यापक-आधारित और बहु-क्षेत्रीय है, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उच्च-प्रौद्योगिकी, असैनिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य शामिल हैं।

परिचय

राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन के नेतृत्व में अमेरिका ने उत्साहपूर्वक भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया। उन्होंने अपने ब्रिटिश सहयोगियों पर भी विजय प्राप्त की, जिसमें प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली भी शामिल थे, जो अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूदा स्थिति के आगे झुक गए। भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। हालाँकि, दोनों देशों ने स्वतंत्रता के बाद के अधिकांश विदेश नीति निर्णयों के विपरीत स्पेक्ट्रम पर खुद को पाया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सक्रिय रूप से भारत को अपने शिविर में शामिल होने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की। भारत ने दृढ़ता से किसी भी शिविर में शामिल होने से इनकार कर दिया और अपनी 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन नीति' को फिर से लागू किया। ऐसा करके, उसने अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' को लागू किया और वर्तमान समय में भी ऐसा करना जारी रखा। भारत को इसकी भारी कीमत तब चुकानी पड़ी जब 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का समर्थन किया और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भी। जब भारत में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा, तो अमेरिका ने खाद्य सहायता (विशेषकर गेहूं) के उसके अनुरोध को

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

|ISSN: 2582-7219|

Volume 2, Issue 6, June 2019

नजरअंदाज कर दिया। उत्तरार्द्ध ने PL-480 कानून का उपयोग करके राष्ट्रों को अपने शिविर में फंसाने की मांग की 1991 में यूएसएसआर के विघटन ने अमेरिका और उसके अन्य सहयोगियों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत किया।अमेरिकी प्रशासन ने इसरो जैसे कई भारतीय संगठनों को मंजूरी दी, और भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को भी भारी मंजूरी मिली। अंत में, 2006 में, दोनों देशों ने प्रसिद्ध भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया।शुरुआत करने के लिए, अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और एक 2+2 संस्थागत संवाद तंत्र है (वर्तमान में, भारत के पास सभी QUAD देशों- जापान और के साथ 2+2 रणनीतिक वार्ता है।) यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में और 'रणनीतिक डोमेन' में अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए दोनों देशों का लगभग एक साझा दृष्टिकोण है।संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत न तो वास्तव में दोस्त हैं और न ही दुश्मन। दोनों देशों के बीच संबंधों में लगातार उतार-चढ़ाव आया है, जो भारत के तटस्थ एन.ए.एम रुख से शुरू होकर कोल्ड वार के दौरान अलग-अलग रास्तों तक और अंतत: रणनीतिक अभिसरण के वर्तमान समय तक चला आया है।[1] 21 वीं शताब्दी में, भारत अमेरिकी भूराजनीति और वैश्विक रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते संबंधों को "21 वीं शताब्दी की एक परिभाषित साझेदारी" के रूप में देखा जा सकता है।[2] यह साझेदारी अमेरिका में बढ़ती भारत की सॉफ्ट पॉवर के रूप में और भी मजबूत हो गई है। जैसा कि जॉन अर्किला ने बिलकुल सही कहा था, कि वर्तमान के वैश्विक युग में विजय ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि किसकी कहानी जीतती है, ना कि इस बात पर की किसकी सेना जीतती है। इस दावे को 1990 में जोसेफ जी नी अपनी “बाउंड टू लीड: द चैलेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पॉवर” नामक किताब में “सॉफ्ट पॉवर” की अवधारणा के माध्यम से उद्घृत किया था।[3] सॉफ्ट पॉवर किसी देश की आकर्षण और सहयोग के माध्यम से और ना कि जबरदस्ती से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इच्छित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में एक निर्णायक वास्तविकता है। सॉफ्ट पॉवर की मुद्रा सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक मूल्य और विदेशी नीतियां हैं। इसी तरह, भारत की सॉफ्ट पॉवर अमेरिकी धरती पर भारतीय प्रवासियों का बढ़ता प्रभाव है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते भारतीयों को "भारतीय-अमेरिकी" कहा जाता है क्योंकि उनकी पैतृक जड़ें भारत में अंतर्निहित हैं। 1980 में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने स्वदेशी अमेरिकियों से पार्थक्य के लिए एक अन्य शब्द गढ़ा ‘एशियाई भारतीय’।[4] अमेरिका में उनका आगमन 1946 के लूसी - सेलर अधिनियम द्वारा चिह्नित हुआ, जिसने भारतीयों को यू.एस की धरती पर देशीकरण अधिकार प्रदान किया।[5] [6] अमेरिका की जनगणना 2010 के अनुसार, एशियाई भारतीयों की आबादी '4.4 मिलियन' है, जो अमेरिका की 308,745,538 की कुल आबादी के लिहाज से ‘69.37%’ की दर से बढ़ रही है।[7] यह संख्या एशियाई भारतीयों को उत्तर अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ती जातीय समुदाय बनाती है जबकि एशियाई भारतीय अमेरिका में मेक्सिकन और चीनी लोगों के बाद तीसरे सबसे बड़े प्रवासी हैं। भारतीय प्रवासी अमेरिका में मुख्य रूप से छात्र प्रवेश कार्यक्रमों, एच-1 बी वीजा कार्यक्रम के लाभार्थियों, परिवार-आधारित वरीयता और अस्थायी श्रमिक वीजा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित हुए हैं। वर्तमान में, भारतीय प्रवासियों का एक बड़ा भाग युवा, उच्च शिक्षित और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.एम) क्षेत्रों में प्रतिष्ठित है। भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में नामांकित दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूह हैं। भारतीय आबादी व्यापक रूप से अमेरिका के सभी स्टेट्स में फैली है जबकि अधिकतर भारतीय कैलिफोर्निया (20%), न्यू जर्सी (11%), टेक्सास (9%), न्यूयॉर्क (7%) और इलिनोइस (7%) में बसे हुए हैं।

भारत-अमेरिका वार्ता

भारत-अमेरिका की दोनों सरकारों के बीच 50 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्र हैं। विदेश मंत्री और राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) के स्तर पर सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता की पहली दो बैठकें सितंबर 2015 में वाशिंगटन डीसी और अगस्त 2016 में नई दिल्ली में आयोजित की गईं थी। इस शीर्ष-स्तरीय वार्ता ने द्विपक्षीय भारत-अमेरिका संबंधों के पांच पारंपरिक स्तंभों में एक वाणिज्यिक घटक जोड़ा है, जिस पर विदेश मंत्रियों की पूर्ववर्ती रणनीतिक वार्ता ने निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित किया था,

- सामरिक सहयोग;
- ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन,
- शिक्षा और विकास;
- अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि; विज्ञान और तकनीक; तथा
- स्वास्थ्य और नवाचार।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

|ISSN: 2582-7219|

Volume 2, Issue 6, June 2019

सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता की दूसरी बैठक 30 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में हुई। इसमें मंत्री स्तरीय संवाद के अलावा निम्न बिंदु शामिल थे:

- होम (होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग),
- वित्त (वित्तीय और आर्थिक भागीदारी),
- वाणिज्य (व्यापार नीति फोरम),
- एचआरडी (उच्च शिक्षा संवाद),
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी पर संयुक्त आयोग की बैठक) और
- ऊर्जा (ऊर्जा संवाद)।

भारत की सॉफ्ट पॉवर का ज़रिया इसके प्रवासी हैं, जो इसकी संपत्ति हैं। भारतीय प्रवासियों का अमेरिका में तीन चरणों में विकास हुआ है, पहला शिक्षा और रोजगार की तलाश, दूसरा, प्रेषण का प्रमुख स्रोत (2017 में यू.एस से भारत में $10.657 बिलियन का वार्षिक प्रेषण) और तीसरा यू.एस की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले प्रभावी खिलाड़ियों के रूप में।[8] अमेरिका के भीतर, भारतीय प्रवासी एक प्रभावी सार्वजनिक कूटनीति उपकरण हैं और अपने नैतिकता, अनुशासन, हस्तक्षेप ना करने और स्थानीय लोगों के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए माने जाते हैं। ये मूल्य अंततः यू.एस में भारतीयों की पहचान बनाने, छवि प्रक्षेपण और छवि बनाने में योगदान करते हैं।[9]

भारतीय प्रवासी ना केवल भारत के सॉफ्ट पॉवर का स्रोत हैं बल्कि भारत के सॉफ्ट पॉवर के अभिकर्ता भी हैं, जैसा कि नीचे चर्चा किया गया है।

संस्कृति - अमेरिका में कई हिंदी रेडियो स्टेशन उपलब्ध हैं जैसे कि आर.बी.सी रेडियो, इजी96 रेडियो, रेडियो हमसफर, देसी जंक्शन, रेडियो सलाम नमस्ते, फनएशिया रेडियो और संगीत।

भारतीय केबल चैनल जैसे कि सोनी टीवी, ज़ी टीवी, स्टार प्लस, कलर्स और क्षेत्रीय चैनल भी प्रसारित होते हैं। कई भारतीय मूल के कलाकार हॉलीवुड का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली कलाकार हैं प्रियंका चोपड़ा, पद्मा लक्ष्मी, फ्रीडा पिंटो, कुणाल नैय्यर, मीरा नायर और मधुर जाफरी। मेट्रोपॉलिटन जिलों की सिनेमाघरों में भी बॉलीवुड फिल्में दिखाई जाती हैं। अधिकांश भारतीय त्योहार उसी उत्साह और जोश के साथ मनाए जाते हैं विशेष रूप से सार्वजनिक समारोहों और बॉलीवुड नृत्य के माध्यम से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है।

धार्मिक भारत के हिंदू (51%), सिख (5%), जैन (2%), मुस्लिम (10%) और ईसाई (18%) समुदायों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दृढ़ता के साथ अपने धर्म को स्थापित किया है। हिंदू भारतीयों ने यू.एस में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का गठन किया है। ये भारतीय धार्मिक समुदाय दान कार्य में सहायता करते हैं जब भी अमेरिका में आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से खालसा फूड पेंट्री और खालसा पीस कॉर्प्स नियमित रूप से अमेरिका में रहने वाले कम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं और किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद के परिदृश्य में भी सहायता करते हैं। 'द सिखसेस' संगठन भोजन और कपड़ों के रूप में और सार्वजनिक सेवा के अवसर पैदा करके सहायता प्रदान करता है।[10]

शिक्षा- भारतीय प्रवासियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, समग्र यू.एस में 25 साल तक की उम्र तक बैचलर्स डिग्री पूरा करने वाले 31% लोगों की तुलना में 79% भारतीय प्रवासी 25 साल की उम्र तक बैचलर्स डिग्री पूरा करते हैं। इसके अलावा, 25 और उससे अधिक आयु वर्ग में अमेरिका की मात्र 11% सामान्य जनता की तुलना में 44% भारतीय प्रवासी मास्टर्स डिग्री, पी.ए.चडी या उन्नत पेशेवर डिग्री अर्जित कर चुके हैं।[11] 2015-16 स्कूली वर्ष में, लगभग 166,000 भारतीय अप्रवासियों को अमेरिका के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला दिया गया था, जो समग्र 1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का 16 प्रतिशत हिस्सा था।[12] वे मुख्य रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.एम) क्षेत्रों में काम करके अन्य नागरिकों को पछाड़ते हैं।

घरेलू आय- भारतीय प्रवासी अमेरिका में सबसे अमीर जातीय समुदायों में से एक है। सभी भारतीय वंशजों की औसत वार्षिक आय लगभग $ 89,000 है, जो कि अमेरिकी नागरिकों की औसत वार्षिक आय $ 50,000 से अधिक है।[13] निवेश आय के मामले में, 15% अमेरिकी लोगों की तुलना में 20% भारतीय परिवारों की कुल आय में लाभांश से मिलने वाली आय शामिल थी, जबकि 43% अमेरिकी नागरिकों की तुलना में 52% भारतीयों को ब्याज से आय मिलती थी।[14] 2000 की अमेरिकी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई भारतीय पुरुष आबादी की "पूरे वर्ष की पूर्णकालिक औसत आय सबसे अधिक थी ($51,094), जबकि एशियाई भारतीय महिलाओं की औसत आय ($ 35,173) थी।[15] भारतीय प्रवासी यू.एस में 50% किफायती लॉज और 35% होटलों के मालिक हैं, जिसका बाजार मूल्य लगभग $ 40 बिलियन है। 2002 में भारतीय प्रवासी अमेरिका के 223,000 से अधिक फर्मों के मालिक थे और $ 88 बिलियन से अधिक की आमदनी करते थे।[16] [17]

राजनीति में भागीदारी- नवंबर 2016 में 5 भारतीय अमेरिकी उम्मीदवारों रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल और कमला हैरिस को यू.एस कांग्रेस में चुना गया, ऐसा करके उन्होंने एक नया इतिहास गढ़ा जबकि एमी बेरा को दूसरी बार चुना गया था। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल करने के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने उनका धन्यवाद करते हुए हिंदुओं की प्रशंसा

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

|ISSN: 2582-7219|

Volume 2, Issue 6, June 2019

करके भारतीय अमेरिकी लोगों की राजनीतिक भागीदारी पर प्रकाश डाला। अमेरिका में 2018 में 60 भारतीय प्रवासी उम्मीदवार संघीय चुनाव, राज्य विधानमंडल और स्थानीय कार्यालय सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में, ट्रम्प के मंत्रिमंडल में लगभग 9 भारतीय अमेरिकी वरिष्ठ सार्वजनिक पदों के प्रभारी हैं जैसे कि श्रीमती निक्की हेली - संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत, कृष्णा आर उर्स - पेरू में अमेरिकी राजदूत, मनीषा सिंह - आर्थिक मामलों के लिए राज्य की सहायक सचिव, नील चटर्जी - संघीय ऊर्जा नियामक आयोग के सदस्य, राज शाह - राष्ट्रपति के उप सहायक और प्रधान उप प्रेस सचिव, विशाल अमीन - बौद्धिक संपदा (आई.पी) प्रवर्तन समन्वयक, नेओमी राव - सूचना और नियामक मामलों के कार्यालय (ओ.आई.आर.ए) की प्रशासक, अजीत वी पाई - संघीय संचार आयोग के अध्यक्ष और सीमा वर्मा - मेडिकेयर और मेडिकऐड सेवाओं के लिए केंद्रों की प्रशासक। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अमेरिकी राजनीति एक रूपांतरण से गुजर रहा है, जहाँ भारतीय मूल के अधिक से अधिक लोग अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से राजनीतिक ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

III. भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियां

“हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी लाभकर वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था” - अल्बर्ट आइंस्टीन

क्रमांक	नाम	यू.एस में उपलब्धि
1.	विनोद धाम	पेंटियम चिप के निर्माता
2.	सत्य नडेला	माइक्रोसॉफ्ट के सी.ई.ओ
3.	इंद्रा नूयी	पेप्सीको के सी.ई.ओ
4.	विनोद खोसला	सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह-संस्थापक
5.	शांतनु नारायन	एडोब सिस्टम में अध्यक्ष
6.	सबीर भाटिया	हॉटमेल के संस्थापक और निर्माता
7.	फ्रांसिस्को डीसूज़ा	कॉग्निजेंट के सी.ई.ओ
8.	सुंदर पिचाई	गूगल क्रोम ब्राउज़र के निर्माता
9.	विवेक गुंडोत्रमन	गूगल+ के डिज़ाइनर
10.	रूचि सांघवी	फेसबुक की पहली महिला इंजिनियर और फेसबुक न्यूज़ फीड की लांचर
11.	अजयपाल सिंह बंगा	मास्टरकार्ड के सी.ई.ओ

- यू.एस में माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मी भारतीय मूल के लोग हैं
- यू.एस.ए में 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं
- ज़ेरॉक्स के 13% कर्मी भारतीय हैं
- यू.एस में नासा के 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं
- आई.बी.एम के 28% कर्मी भारतीय मूल के लोग हैं
- यू.एस.ए में 38% डॉक्टर्स भारतीय हैं
- इंटेल के 17% वैज्ञानिक भारतीय हैं[18]

विचार-विमर्श

भारत-अमेरिका संबंधों में चुनौतियां

ईरान और रूस के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों को संतुलित करने में चुनौतियां रही हैं। भारत को ईरान और रूस से रियायती तेल आयात को रोकने के लिए मजबूर किया गया है, और इन भारी-भरकम अमेरिकी रणनीति के कारण भारत के तेल आयात बिल में तेज वृद्धि हुई है। भारत-अमेरिका के हित तब टकरा गए जब भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद रूसी निर्मित S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली का फैसला किया। भारत अमेरिका संबंधों में अन्य निम्न प्रकार से हैं:

अमेरिका-पाकिस्तान संबंध: भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को डी-हाइफ़न करने के वाशिंगटन के दावों के बावजूद, अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने जटिल गठबंधन की देनदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर पाया है।व्यापार विवाद अमेरिका ने हाल ही में भारत को अपने सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम से हटा दिया, जिसका भारत एक बड़ा लाभार्थी था। अमेरिका ने भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाले स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क लगाया

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

|ISSN: 2582-7219|

Volume 2, Issue 6, June 2019

भारत को अमेरिका द्वारा "टैरिफ किंग" के रूप में संदर्भित किया गया है जो "अत्यधिक उच्च" आयात शुल्क लगाता है।डब्ल्यूटीओ विवाद: भारत यूएसए, भारत द्वारा चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को सीमित करना, अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों आदि के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच जैसे मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ विवादों में शामिल है।आईपीआर संघर्ष: भारत अमेरिका की "प्राथमिकता निगरानी सूची" में भी है जो अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए चुनौतियों का सामना करने वाले देशों की पहचान करता है। भारत के लिए करेंसी मैनिपुलेटर टैग - हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की 'निगरानी सूची' में शामिल किया।भारत में आंतरिक मुद्दे: अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी नागरिक समाज के कुछ हिस्सों की आलोचना अमेरिकी प्रशासन को भारत को कश्मीर को सामान्य स्थिति में लाने और एनआरसी के बाद नए नागरिकता कानून के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए कह रही ।अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मानवाधिकार रिपोर्ट - उल्लेख किया गया है कि भारत में कई मानवाधिकार मुद्दे हैं जैसे कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, हिंसा से जुड़े अपराध और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को लक्षित करने वाले भेदभाव आदि।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाले देश (सीपीसी) के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की। इसने भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं पर 'धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन' के लिए लक्षित प्रतिबंधों की भी सिफारिश की। अमेरिका ने नई दिल्ली से अनुमति लिए बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन (FONOP) किया।21वीं सदी में विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच संबंध महत्वपूर्ण हैं। सहयोग की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, दोनों सरकारों को अब अधूरे समझौतों को अंतिम रूप देने और व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संबंध को फलने-फूलने के लिए विभिन्न राजनयिक विकल्पों के साथ निरंतर पोषित किया जाना चाहिए।

हाल के समय में नई दिल्ली की ओर दौड़ लगाते दुनिया भर के राजनयिकों, अधिकारियों और मंत्रियों की लंबी सूची को देखें तो एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की भूमिका का अनुमान लगाना पर्याप्त आसान हो जाता है।अमेरिका के संदर्भ में देखें तो भारत बाइडेन प्रशासन की 'इंडो-पैसिफिक' रणनीति का केंद्रबिंदु है और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ '2+2' बैठक में भाग लिया है।यद्यपि दोनों देश रूस-यूक्रेन संघर्ष—जो अभी वैश्विक भू-राजनीति के सबसे चिंताजनक मुद्दों में से एक है, पर एकसमान दृष्टिकोण नहीं रखते, किंतु मतभेदों से ऊपर उठना और निरंतर सहयोग सुनिश्चित करना दोनों देशों के पारस्परिक हित में है। भारत-अमेरिका संबंधों का विस्तार और गहनता अपूर्व है और इस साझेदारी के प्रेरक तत्व अभूतपूर्व वृद्धि कर रहे हैं।यह संबंध अभी तक अद्वितीय बना रहा है क्योंकि यह दोनों स्तरों पर संचालित होता है: रणनीतिक अभिजात वर्ग के स्तर पर भी और लोगों के आपसी संपर्क के स्तर पर भी।यद्यपि रूस-यूक्रेन संकट के प्रति भारत और अमेरिका की प्रतिक्रियाएँ पर्याप्त विरोधाभासी रहीं, हाल की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह मत व्यक्त किया कि दुनिया के दो प्रमुख लोकतंत्र पारस्परिक रूप से स्वीकार्य परिणामों पर पहुँचने के लिये अपने मतभेदों को दूर करने के इच्छुक हैं।भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में संबंधों में आई गर्माहट पर आगे बढ़ते रहने और व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण को न खोने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।इस वार्ता में 'स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किये गए क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में सहयोग को गहरा करना चाहते हैं ताकि इन दोनों ही 'वॉर-फाइटिंग डोमेन' में क्षमताओं को विकसित किया जा सके।वे संयुक्त साइबर प्रशिक्षण एवं अभ्यास का विस्तार करते हुए एक आरंभिक 'रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वार्ता' (Defence Artificial Intelligence Dialogue) आयोजित करने पर भी सहमत हुए।भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी भी तेज़ी से बढ़ रही है जहाँ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया है कि दोनों देशों ने "हिंद-प्रशांत के वृहत भूभाग में हमारी सेनाओं की परिचालन पहुँच का विस्तार करने और अधिक निकटता से समन्वय करने के लिये नए अवसरों की पहचान की है।" अमेरिका ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख भी किया कि चीन भारत के साथ सीमा पर 'दोहरा उपयोग अवसंरचना' (dual-use infrastructure) का निर्माण कर रहा है और यह भारत के संप्रभु हितों की रक्षा के लिये उसके साथ खड़ा रहेगा।अमेरिका में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच संबंधों की पुनः रचना में योगदान दे रहा है। भारत दो कारणों के आधार पर भारतीय-अमेरिकियों के अविर्भाव को एक प्रतिष्ठित समुदाय के रूप में मान्यता देता है।

पहला, भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिकी चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में सामने आए हैं। दूसरा, भारतीय-अमेरिकी लोग काफी शिक्षित और बेहद अमीर हैं। जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक शक्ति में हिस्सेदारी के साथ, भारतीय अमेरिकी पैरवी का ध्यान भारत की समस्याओं की ओर झुक गया है। उदाहरण के लिए, अप्रवासन कानून के संबंध में, भारतीय प्रवासियों ने यू.एस की 1965 अप्रवासन नीति में भारतीयों के लिए अप्रवासन कानूनों के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।[19]अगला है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा की गई पैरवी के प्रयासों के कारण ही भारत पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी नीति को निष्क्रिय किया जा सका। परिणामस्वरूप, एन.एस.जी द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंध (1998 के परमाणु प्रसार के बाद) को अमेरिका की सिफारिश पर हटा दिया गया था।[20] अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

|ISSN: 2582-7219|

Volume 2, Issue 6, June 2019

भारत के दौरे के दौरान खुद ही प्रतिबंध हटाने पर प्रवासी भारतीयों के दबाव का ज़िक्र किया था।[21] एक और उदाहरण है भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग सहमति को अंतिम रूप देने में भारतीय प्रवासियों की उल्लेखनीय अनुनय। इस '123 सहमति' की पुष्टि जुलाई 2007 में हुई और अक्टूबर 2008 में इस पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे भारत अप्रसार संधि के सभी प्रावधानों का लाभ उठाने में सक्षम हो सका।[22]

अमेरिका में भारत की सॉफ्ट पॉवर का लक्ष्य सामरिक प्रकृति का है। भारतीय अमेरिकी लोग दबाव बनाकर और प्रचार-प्रसार करके अमेरिका सरकार के अधिकारियों को अधिक सहायक और संवेदनशील बनने के लिए राजी करवा रहे हैं। यू.एस.ए से आने वाली एफ.डी.आई पर्याप्त नहीं है और संभावित अपेक्षा और आवश्यकता से कम है। इसलिए, अमेरिका से पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जब्त करने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा कुशल पैरवी महत्वपूर्ण है।[23] वह दूसरा क्षेत्र जिसमें भारतीय प्रवासियों ने भारत की सहायता की है, वो है "विदेशी शिक्षा प्रदाता विधेयक, 2010" के तहत शैक्षिक भेदभाव से उभरना, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अनुमोदन प्रदान किया था। भारतीय प्रवासियों की पैरवी अमेरिकी सरकार को भारत में अमेरिकी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना द्वारा सहयोग करने के लिए राजी कर सकती है। भारत की घरेलू और वैश्विक स्तर पर विविध आकांक्षाएं हैं जिनके लिए विशाल विदेशी पूंजी और अभिस्वीकृति की बहुत आवश्यकता है।[24]

परिणाम

मज़बूत भारत-रूस संबंध: भारत-अमेरिका संबंध में रूस कोई नया कारक नहीं है। प्रतिबंधों के बीच भी भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में कमी लाने के बजाय वृद्धि ही की है। रूस द्वारा भारत के लिये कम मूल्यों पर इसकी पेशकश की गई थी।भारत-रूस रक्षा संबंध भी भारत-अमेरिका संबंधों में एक अवरोध बना रहा है।भारत द्वारा रूस से 'S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली' की खरीद पर अमेरिकी CAATSA कानून के अनुपालन को लेकर भी लंबे समय से चर्चा जारी है।हालाँकि अमेरिका स्पष्ट रूप से यह भी समझता है कि भारत पर प्रतिबंध लगाने जैसा कोई भी कदम उनके संबंधों को फिर दशकों पीछे घसीट ले जाएगा।अमेरिका की स्पष्ट चेतावनी (कि जो देश रूस पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने या किसी प्रकार उसकी पूर्ति करने का सक्रिय प्रयास करेंगे, परिणाम भुगतेंगे) के बावजूद भारत और रूस डॉलर-आधारित वित्तीय प्रणाली को दरकिनार कर द्विपक्षीय व्यापार कर सकने के तरीके तलाश रहे हैं।चीन के साथ सहयोग की भारत की संभावनाएँ: हाल के वर्षों में चीन ने अपनी अमेरिकी नीति के चश्मे से भूभाग में भारत के किसी भी कदम की समीक्षा की है, लेकिन यूक्रेन पर भारत के रुख के बाद बीजिंग में एक पुनर्विचार की शुरुआत हुई है।हाल में चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा एक वृहत रणनीतिक 'रीसेट' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जो भारत को 'क्वाड' से दूर करने की आवश्यकता से प्रेरित था।अपनी यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने दक्षिण एशिया में भारत की पारंपरिक भूमिका की रक्षा के साथ ही 'चीन-भारत प्लस' (China-India Plus) के रूप में विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने का दृष्टिकोण प्रकट किया और इसके लिये एक वर्चुअल G-2 के निर्माण की पेशकश की।जबकि म्याँमार, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भारतीय और अमेरिकी नीतियाँ भिन्न हैं, चीन ऐसा विषय है जो दोनों देशों को एक साथ जोड़ता है।यदि अभी चीन के साथ भारत के संबंधों के पुनर्निर्माण का अवसर बनता है तो यह अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को बदल देगा और 'क्वाड' की प्रभावशीलता पर सवाल उठाएगा।

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग: राजनीतिक मामलों की अमेरिकी विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान स्वीकार किया कि "रक्षा आपूर्ति के लिये रूस पर भारत की निर्भरता महत्त्वपूर्ण है" और यह "उस युग में सोवियत संघ और रूस से सुरक्षा समर्थन की विरासत है जब अमेरिका भारत के प्रति कम उदार रहा था।"हालाँकि, आज की नई वास्तविकताओं के साथ इस द्विपक्षीय संलग्नता के प्रक्षेपवक्र के आकार लेने के साथ यह उपयुक्त समय होगा जब अमेरिका भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ-साथ सह-उत्पादन और सह-विकास के माध्यम से अपना रक्षा विनिर्माण आधार बनाने में मदद करे।अवसरों की खोज: भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में—जो एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। यह अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग अपने महत्त्वपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिये कर सकता है।भारत और अमेरिका आज इस संदर्भ में सही अर्थों में रणनीतिक साझेदार हैं कि यह परिपक्व प्रमुख शक्तियों के बीच ऐसी साझेदारी है जो पूर्ण अभिसरण की तलाश नहीं कर रही है, बल्कि निरंतर संवाद सुनिश्चित कर और असहमतियों को नए अवसरों को गढ़ने में निवेश कर मतभेदों का प्रबंधन कर रही है।सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग: यूक्रेन संकट के परिणामस्वरूप चीन के साथ रूस का बढ़ा हुआ संरेखण चीन से मुकाबले के लिये केवल रूस पर भरोसा कर सकने की भारत की क्षमता को जटिल बनाता है। इसलिये अन्य सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग जारी रखना दोनों देशों के हित में है।चीनी सेना की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को लेकर व्याप्त चिंताएँ अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों में अंतरिक्ष शासन को भी एक प्रमुख विषय बनाती है। भारतीय प्रवासियों का अभूतपूर्व ढंग से विकास हुआ है, 1960 और 1970 के दशक में पहली पीढ़ी के एक छोटे एवं अराजनैतिक समूह के आप्रवासियों से लेकर 21 वीं शताब्दी में अमेरिकी समाज का एक आर्थिक और सामाजिक रूप से सुस्थापित हिस्सा बनने तक। प्रवासी भारतीयों ने निस्संदेह ही अग्रणी, अशिक्षित और कम कुशल पंजाबी किसानों से ऊपर

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

|ISSN: 2582-7219|

Volume 2, Issue 6, June 2019

उठकर वर्तमान में अधिक कुशल तीन मिलियन लोगों का एक मजबूत समुदाय बनाने की लंबी दूरी तय की है।[25] भारतीय अमेरिकी सबसे धनी (जिनकी घरेलु आय अमेरिका के लोगों के औसत आय का लगभग दोगुना है), सबसे शिक्षित और अमेरिका में कानून का पालन करने वाला जातीय समुदाय है, जो एक "आदर्श अल्पसंख्यक" है।[26] ये समुदाय काफी संगठित भी है। इनमें से काफी लोग भारत की नियमित यात्रा करता है और कई लोग देश में प्रेषण भेजते हैं। भारतीय अमेरिकियों ने कई वकालती संगठनों और राजनीतिक कार्य समितियों की स्थापना की है जिन्होंने भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों के पक्ष में कई बुनियादी कार्य किया है। उदाहरण के लिए, यू.एस-भारत राजनैतिक कार्य समिति, भारतीय महासंघ और भारतीय अमेरिकी राजनैतिक शिक्षा मंच ने निष्पक्ष और संतुलित नीतियों को बढ़ावा देने में सहायता की है और भारतीयों के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रवेश करने का रास्ता आसान बनाया है।[27] ये संगठन विशेष रूप से कानूनी अप्रवासन, आतंकवाद के खिलाफ जंग, व्यापारिक संबंध, वैश्विक स्वास्थ्य, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और अमेरिका-भारत व्यापार के मामलों को संभालती है। सीनेट इंडिया कॉकस और भारत और भारतीय अमेरिकियों की कांग्रेसनल कॉकस – कांग्रेस की दोनों सदनों में भारत का द्विदलीय कॉकस है। उनकी छोटी आबादी को देखते हुए, भारतीय अमेरिकी समुदाय का प्रभाव आबादी के आकार की तुलना में अनुपातहीन है क्योंकि समुदाय के सदस्य दोनों दलों के प्रमुख वित्तीय योगदानकर्ता बन गए हैं। जिन लोगों को कभी सपेरा माना जाता था, अब उन्हें यू.एस में बढ़ती सॉफ्ट पॉवर के लिए जाना जाता है।भारतीय अमेरिकियों की समृद्ध सभ्यता और सांस्कृतिक लोकाचार अमेरिकी ताने-बाने का हिस्सा बन गया है, जहाँ दोनों देश भारतीय प्रवासियों को एक-दूसरे के लिए लाभकर मानते हैं। भारत की संस्कृति का प्रसार करने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका गैर-सरकारी सार्वजनिक राजनयिकों और सांस्कृतिक राजनयिकों के माध्यम से राष्ट्र की ब्रांडिंग में भी योगदान दे रही है।[28]

संदर्भ

1 द डिप्लोमेट, भारत के लिए अगला कदम क्या – यू.एस संबंध?, 10 जुलाई 2018
2 बरैक ओबामा, 21 वीं शताब्दी की एक सुनिश्चित साझेदारी, 2010
3 जोसफ एस नाइ जूनियर, वैश्विक राजनीती सार्वजनिक मामलों में सफलता की कुंजी सॉफ्ट पॉवर, 2005
4 रिसर्च गेट, भारतीय प्रवासियों पर रूलेह हैंडबुक,
5 संयुक्त राष्ट्र बनाम भगत सिंह थिंड
6 अप्रवासन और कानून, अप्रवासन की राजनीती, 2018
7 यू.एस सेन्सस बोर्ड, 2010
8 यू.एस में भारतीय प्रवासी महत्वपूर्ण क्यों हैं, द इकनोमिक टाइम्स, 2018
9 भारतीय प्रवासी: जनजातीय और प्रवासी पहचान, सी.ए.आर.आई.एम भारत, 2013
10 हिन्दू अमेरिकी सेवा कार्यों ने हिन्दू स्वयंसेवकों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, हफपोस्ट, 2012
11 मुज़फ्फर एच सैय्यद, भारत-यू.एस संबंध, 2012
12 एम.पी.आई, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय प्रवासी, 2014
13 मुज़फ्फर एच सैय्यद, भारत-यू.एस संबंध. 2012
14 आई.बी.आई.डी
15 आई.बी.आई.डी
16 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय प्रवासी, शोधगंगा
17 एम.पी.आई, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय प्रवासी, 2014
18 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीयों की उपलब्धि, यू.एस.ए वीजा टॉक, 2013
19 एरिका ली, अप्रवासी और अप्रवासन कानून: क्षेत्र आंकलन की एक अवस्था, 1999
20 राष्ट्रीय भारतीय अमेरिकी महासंघ (एन.एफ.आई.ए), 2012
21 द इकनोमिक टाइम्स, यू.एस ने 22 सालों तक भारत को अनदेखा किया, क्लिंटन के दौरे ने सब कुछ बदल डाला: चटवाल, 2010
22 एम.आई.टी, यू.एस-भारत परमाणु सौदा और भारतीय प्रवासियों की भूमिका, 2008
23 भारतीय प्रवासियों से एफ.डी.आई नीति, 2009
24 आयन हॉल, भारत की नई सार्वजनिक कूटनीति: सॉफ्ट पॉवर और सरकार की कार्रवाइयों की सीमाएं, 2012
25 ओ.आर.एफ,यू.एस निर्वाचन, भारतीय प्रवासियों की भूमिका का स्पष्टीकरण, 2015
26 ऊमा पुरुषोत्तम, यू.एस निर्वाचन, भारतीय प्रवासियों की भूमिका का स्पष्टीकरण, 2015
27 आई.ए.सी.सी, यू.एस-भारत के आर्थिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना
28 कामनी कुमारी, सॉफ्ट पॉवर के रूप में प्रवासी: यू.एस में भारतीय प्रवासियों की एक केस स्टडी, 2017